संपादकीय

सहयोग संग सावधानी

भारत और चीन के बीच बुधवार को हुई विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में बनी सहमति इस बात का ठोस संकेत है कि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले चार साल से आया ठहराव धीरे-धीरे दूर हो रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और इससे जुड़े कई किंतु-परंतु कायम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान हुई मुलाकात के बाद से मतभेद दूर करने की प्रक्रिया में जो तेजी आई, उसका असर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बने माहौल पर भी दिखा। पांच साल के अंतराल पर हुई विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में सहमतियों पर अमल की तो पुष्टि हुई ही, यह संकेत भी मिला कि अब दोनों पक्ष इससे आगे बढ़ने को तैयार हैं। बॉर्डर ट्रेड, ट्रांस बॉर्डर नदियों पर डेटा शेयरिंग और मानसरोवर यात्रा की संभावनाएं वाकई उत्साह बढ़ाने वाली हैं। जैसे-जैसे सीमा संबंधी मसलों पर सहमति बन रही है और वहां माहौल सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, दोनों देशों के रुख में सहयोग पर जोर भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे, चीन का काफी समय से आग्रह रहा है कि एलएसी से जुड़े मसलों को एक तरफ करके सहयोग बढ़ाया जाए, लेकिन भारत अपने इस रुख पर अडिग रहा कि जब तक एलएसी पर हालात सामान्य नहीं होते, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे में यह गौर करने वाली बात है कि अब भारत की तरफ से भी सहयोग का दायरा बढ़ाने की संभावना पर पॉजिटिव रुख दर्शाया जा रहा है। इस बात को भी कुछ हलकों में रेखांकित किया गया है कि संबंधों में सुधार और बातचीत में प्रगति को व्यक्त करने के दोनों पक्षों के तरीकों में पूरी तरह समानता नहीं है। मिसाल के तौर पर, बातचीत के बाद दोनों तरफ से जो अलग-अलग बयान जारी किए गए, उनमें अंतर है। जहां चीन के बयान में स्पष्ट शब्दों में सर्वसम्मति के छह बिंदु गिनाए गए हैं, वहीं भारत के बयान में इन्हें सर्वसम्मति करार देने से बचा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को ही जारी पेंटागन की सालाना रिपोर्ट की यह बात भी गौर करने लायक है कि चीन ने न तो गलवान घाटी में जून 2020 को हुई सैन्य झड़प के बाद इस क्षेत्र में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती में कोई कमी की है और न ही टैंकों, मिसाइलों व अन्य भारी हथियारों की संख्या में कोई कटौती की है। हालांकि अभी उस इलाके से सैन्य वापसी की प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है, लेकिन फिर भी चीन के पिछले रेकॉर्ड को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था - जय जवान जय किसान! अर्थात देश की रक्षा करने वाले सैनिक जवान हमारे लिए सम्माननीय हैं ,तो वहीं देश का पेट भरने वाले किसान भी उतने ही आदरणीय हैं। शायद उसे वक्त किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक सैनिक तो एक देश विशेष की रक्षा के लिए दूसरे देश के इंसान को मौत के घाट उतार कर अपनी देश भक्ति का परिचय देता है। वहीं एक किसान तो बिना कोई भेदभाव किया हर इंसान के लिए अन्न उपजाता है। अर्थात वह पूरे इंसानियत की सेवा करता है। इस मायने में किसान तो देवतुल्य हो जाता है। आज यह हालत है कि इस देवता की हालत ही सबसे दयनीय है। देश की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की गरीबी व पिछड़ापन। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं। इन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य का नही मिलना, दूसरे कृषि के उन्नत एवं सस्ते साधनों का अभाव होना, तीसरे किसानों और सरकार के बीच सीधा संबंध ना होना।

सब का पेट भरने वाला किसान कहीं स्वयं भूखा तो नहीं...?

सुरेश सिंह बैस -शाश्वत-

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है। अर्थात हमारे देश का अधिकतर वर्ग किसान की श्रेणी में आता है! फिर भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, औद्योगिक वातावरण, कुशल श्रम सभी कुछ आवश्यक तत्वों के होते हुए भी आज का किसान इतना दयनीय है कि वह धीरे-धीरे किसानी जैसे जीविकोपार्जन से निराश होकर अन्य जीविकोपार्जन के लिए साधन खोजने पर विवश हो गया है। कहीं सबका पेट भरते भरते वह स्वयं ही तो भूखा नहीं रह जा रहा है यह यक्ष प्रश्न आज व्यवस्था के लिए अत्यंत विचारणीय है,और इसका समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था - जय जवान जय किसान ! अर्थात देश की रक्षा करने वाले सैनिक जवान हमारे लिए सम्माननीय हैं ,तो वहीं देश का पेट भरने वाले किसान भी उतने ही आदरणीय हैं। शायद उसे वक्त किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक सैनिक तो एक देश विशेष की रक्षा के लिए दूसरे देश के इंसान को मौत के घाट उतार कर अपनी देश भक्ति का परिचय देता है। वहीं एक किसान तो बिना कोई भेदभाव किया हर इंसान के लिए अन्न उपजाता है। अर्थात वह पूरे इंसानियत की सेवा करता है। इस मायने में किसान तो देवतुल्य हो जाता है। आज यह हालत है कि इस देवता की हालत ही सबसे दयनीय है। देश की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की गरीबी व पिछड़ापन। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं। इन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य का नही मिलना, दूसरे कृषि के उन्नत एवं सस्ते साधनों का अभाव होना, तीसरे किसानों और सरकार के बीच सीधा संबंध ना होना। यही तीन मुख्य कारण हैं जो हानिकारक साबित हो रहे हैं। बीच के व्यापारी- दलाल आदि इनका शोषण कर सरकार को भी आर्थिक चपत लग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह सीधे किसानों से उनके उपज का विक्रय करने की व्यवस्था करें! तभी उन्हें बिचौलियों एवं व्यापारियों की बनी हुई इस गलत व्यवस्था पर काबू पाने में आसानी हो सकती है। क्रय विक्रय के बीच बिचौलियों की भूमिका सर्वथा खत्म कर देनी आवश्यक है। एक बहुत बड़ी विवशता आज किसानों के साथ चल रही है। वह यह कि प्रत्येक व्यवसायी या विक्रेता को अपने विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। पर किसान को अब भी उसके उपज का विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिल पाया है। जबकि वह अपनी उपज के तैयार होने के दौरान के सभी जोखिम, प्राकृतिक विपदाओं को स्वयं अकेले के बलबूते पर ही झेलता है। परिणामस्वरूप एक किसान को उसके उपज का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता जो उसके लिए घाटे का सौदा बन जाती है। और वह पुनः इन व्यापारियों या ठेकेदारों के पास एक कर्जदार के रूप में उनका चिर ऋणी बना दिया जाता है। किसान का यह अप्रत्यक्ष शोषण न जाने कब से चला आ रहा है। इस परंपरा को अब बंद करने के लिए अब सरकारी स्तर पर कुछ ठोस पहल होना चाहिये। अगर देश का विकास करना है तो इस अधिसंख्य वर्ग के विकास के लिये सार्थक पहल उतनी ही जरूरी है, जितना अन्य व्यावसायिक कार्य। सरकारी उपक्रमों से भी किसानों को अपने कृषि कार्य के उचित संपादन के लिये खाद, बीज, ऋण, हल, बैल व अन्य साधनों को मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। हां ये भी सच है कि इन्हें वह सब प्राप्त होता है पर ऊंचे ब्याज दर के बाद और वह फिर जब अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के बाद भी ऋण को नहीं पटा पाता है तो उसके जीविका का मुख्य स्रोत खेत और खलिहान ही जप्त किया कर लिए जाते हैं । किसानों की दयनीय हालात को दूर करने के लिए कृषि का भरपूर विकास किया जाना भी अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। कृषि के विकास के लिए जरूरी है कि सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज, पशुपालन, पर्याप्त खाद एवं उर्वरक तथा प्रभावी कीटनाशक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हों। किसानों का मानसिक विकास भी आवश्यक होगा। जब तक इनमें नूतनता को ग्राह्य करने की शक्ति पैदा नहीं हो जाएगी इनकी आधुनिकीकरण में रुचि नहीं होगी। कृषक को स्वावलंबी बनाने के लिए जरूरी है कि कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़े होने से बचाया जाए। यदि कृषि भूमि अपना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो फिर वह अनुपयोगी हो जाएगी। और अंतत उसे (जीविका) त्याग कर किसान मजदूरी करने या रोजी-रोटी के लिए अन्य उपाय अपनाने को बाध्य हो जाएगा।

इनका पिछड़ापन दूर करने के लिए शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। साथ ही निर्बल वर्ग के अधिकारों को सरकार की ओर से संरक्षण भी जरूरी है। किसानों की प्रगति पर दृष्टि डालने से ऐसा एक भी पहलू नजर नहीं आता, जिस पर हम गर्व कर सकें। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो प्रदेश में सब कुछ होने के बावजूद भी किसान अपेक्षाकृत प्रगति नहीं कर पाया है। जिसका एक ही कारण है कुप्रबंधन। सक्षम प्रबंधन खराब से खराब स्थिति में भी प्रगति के द्वार खोल देता है। पंजाब व हरियाणा के किसानों की प्रगति इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुजरात व महाराष्ट्र में हुई प्रगति भी क्षमता पूर्ण प्रबंधन से ही संभव हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई का उदाहरण लें, हमारे कुछ प्रदेशों की सिंचाई क्षमता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। सिंचाई के भरपूर साधनों के बावजूद हम सिंचाई के मामले में राष्ट्रीय औसत से अभी काफी पीछे हैं। इसके विपरीत जो कुछ सिंचाई क्षमता निर्मित हो पाई है, उनका भी पूरी तरह से दोहन उपयोग नहीं हो पा रहा है। कहीं-कहीं तो उपयोग की क्षमता तीस या चालीस प्रतिशत से भी कम है। यदि इस तरह की स्थिति है तो उसके लिए प्रबंधन की क्षमता ही उत्तरदाई है। किसानों को शिकायत रहती है कि बिजली, पानी, बीज, खाद आदि के लिए वे तहसील, जिला कलेक्टर और आवश्यक हो तो सचिवालय के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। इस दौरान किसानों के समय का मूल्य नहीं समझा जाता। जनशक्ति का ऐसा अपव्यय संभवत किसी स्वतंत्र देश में नहीं होता होगा। इतिहास गवाह है के ऐसे देश का पतन अवश्य संभावित है। जनशक्ति नियोजन की प्रक्रिया उस समय तक अधूरी रहेगी ,जब तक किसानों को जायज मजदूरी और उनके समय के मूल्य को नहीं पहचाना जाएगा। वहीं कृषि के आधुनिक तौर तरीके अपनाने में भी आज का किसान पिछड़ा हुआ है इसमें अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं किए गए हैं। यदि प्रयत्न किए गए होते तो आज किसानों की स्थिति बहुत अच्छी होती। हरियाणा में तो कृषि के बलबूते पर विकास की गति बढी है, और इसके लाभ किसानों तक पहुंचे भी हैं। हरियाणा और पंजाब ने गत वर्षों के भीतर कृषि के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। आज यहां गन्ना ,गेहूं और बासमती धान से बाजार भरा पड़ा है। निर्धन प्रांत बंगाल तक के गांव में धान की पैदावार पहले से दुगनी कर ली गई है। अब समय आ गया है कि देखना होगा कि कृषि, सिंचाई और गरीबी की रेखा को तोड़ने के लिए कितना कुछ किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ राज्यों के कृषि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संकाय कृषकों की समृद्धि में कितना योगदान दे रहे हैं। सरकारी उपक्रम और भारी भरकम निगम राज्य और अंततः कृषकों पर बोझ तो नहीं बन गए हैं। कृषक जगत को मुक्त बाजारू प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ देने से हानि होगी या लाभ यह निश्चित ही देखना होगा। वैसे भी राजनीतिक लाभ के लिए अनैतिक रूप से लगान और सिंचाई माफी चाहे जिले को अकाल ग्रस्त घोषित कर या मुफ्त अनाज देने की प्रवृत्ति अपनाकर सरकारें अनैतिकता का ही तो परिचय दे रही हैं। उसके भावी परिणाम क्या होंगे। क्या इस देश के नेतागण व सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करती हैं...? यह हम सब के सम्मुख प्रश्नचिन्ह लगाता है।

जाने सर्दियों में कैसे रखें त्वचा का ध्यान

(डॉ.फौजिया नसीम-शाद-विभूति फीचर्स)

इसमें इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि सर्दियों के मौसम में त्वचा संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण इस मौसम में एक्स्ट्रा स्किन केयर की आवश्यकता होती है, उपरोक्त लेख में सर्दियों के मौसम में भी प्रॉब्लम फ्री स्किन के लिए कुछ उपयोगी टिप्स दिये जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप भी नमी चुराती इन सर्दियों में नरम, मुलायम चमकदार स्किन के साथ खुल के मुस्कुरा सकती हैं।

प्रॉब्लम फ्री स्किन के लिए अपनाएं ये तरीके-

- स्किन को साबुन से धोने के विपरीत अच्छी क्वालिटी वाले फेसवॉश का प्रयोग करें।
- स्किन को सदैव गुनगुने पानी से धोएं।
- स्किन क्लींज़र के रूप में शहद का प्रयोग कर सकती हैं
- स्किन पर कोई प्रॉब्लम न हो इसके लिए स्किन की रूटीन केयर का विशेष ध्यान रखें।
- नॉर्मल स्किन के लिए ग्लिसरीन युक्त या माइश्चराइज़र वाले साबुन का प्रयोग ठीक रहता है।
- ऑयली स्किन के लिए मेडिमिक्स या नीम साबुन आदि का प्रयोग लाभदायक रहता है ।
- स्किन सैल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल, सब्जियों और दालों का सेवन करें।
- आंखों के आसपास की स्किन अधिक सेंसेटिव होती है इसलिए अच्छी क्वालिटी की आईक्रीम का प्रयोग करें।
- ग्लोइंग स्किन पाने के लिए भरपूर नींद के साथ पानी का भी भरपूर सेवन करें।
- स्किन को यूवी. किरणों से बचाने के लिए यू.वी.ए. प्रोटेक्टिव सन स्क्रीन का प्रयोग अवश्य करें।
- प्रॉब्लम फ्री स्किन के लिए केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कम से कम करें।
- स्किन हैल्दी रहे इसके लिए ऑयली जंक फूड का सेवन कम करें।
- स्किन हैल्दी और आकर्षक रहे इसके लिए सोने से पूर्व मेकअप को रिमूव अवश्य करें।
- स्किन में नमी स्थापित रहे इसके लिए माइश्चराइजर का प्रयोग अवश्य करें।

शीतकालीन सत्र में 84 करोड़ स्वाहा!

(उत्कर्ष गहरवार)

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। सत्र में संविधान दिवस मनाया गया। दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। सत्र में काफी हंगामा भी हुआ। बी आर अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। लोकसभा की कार्यक्षमता लगभग 58 प्रतिशत रही। राज्यसभा की कार्यक्षमता केवल 40 प्रतिशत रही। सत्र में पाँच विधेयक लोकसभा में पेश हुए। चार विधेयक पारित हुए।

संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को हंगामे के बीच खत्म हो गया। इस सत्र में संविधान पर अच्छी बहस हुई। साथ ही दो अहम बिल भी पेश किए गए। एक बिल एक साथ चुनाव कराने के बारे में था। लेकिन बीआर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई। इस वजह से सत्र का अंत कड़वाहट भरा रहा।सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दलों के बीच तनाव बना रहा। गुरुवार को हुई तीखी बहस के बाद दोनों पक्षों में कटुता बढ़ गई थी। इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही तीन मिनट के भीतर स्थगित करनी पड़ी। सत्र के अंत में होने वाली सारांश चर्चा भी नहीं हो पाई।

राज्यसभा में भी स्थिति कुछ ख़ास बेहतर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के आंबेडकर के कथित अपमान पर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी विदाई भाषण पढ़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्यसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 58 प्रतिशत

लोकसभा सचिवालय के अनुसार,सदन की उत्पादकता लगभग 58 प्रतिशत रही। यह उन दिनों से काफी कम है जब यह 100 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा होती थी। अपनी समापन टिप्पणी में,जगदीप धनखड़ ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और संसदीय मर्यादा बहाल करने का आह्वान किया। विपक्ष के इस आरोप के बीच कि वे अक्सर पक्षपातपूर्ण रहे हैं,उन्होंने संतुलित रुख अपनाया। धनखड़ ने कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सदन ने प्रभावी ढंग से केवल 43 घंटे और 27 मिनट काम किया। इस सत्र की उत्पादकता मात्र 40.03 प्रतिशत रही।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले से हुए समझौते के बावजूद विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ही उत्पादकता कम रही। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी थी। रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को इस चिंताजनक स्थिति पर विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वे विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी रखेंगे।

लोकसभा में पांच बिल पेश,राज्यसभा में तीन

इस सत्र के दौरान लोकसभा में पांच विधेयक पेश किए गए,जिनमें से चार पारित हुए। राज्यसभा ने तीन विधेयक पारित किए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 'संविधान सदन' में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। यह सत्र भारतीय संविधान की महत्ता को दर्शाता है। इस सत्र में संविधान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा हुई।

इस सत्र में एक साथ चुनाव कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। हालांकि, इस बिल पर सभी दलों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। 20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज ना होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ है। यह वो पैसे हैं,जो हमारे आपके टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपये खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती रहती हैं। संसद के हालिया सत्र में काफी कम कामकाज हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही काम हुआ। यह बहुत कम समय है और इसका मतलब है कि संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई।

आधा क्विंटल सोना और 11 करोड़ कैश, म.प्र.में बढ़ते भ्रष्टाचार का नमूना ही तो है

अमित शाह ने कहा - हमे तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ-साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये भी बताता हूं। अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं ।

(मुनेश्वर कुमार)

आधा क्विंटल सोना, करोड़ों रुपए कैश... एक अदना सा कॉन्स्टेबल अपनी सैलरी से तो इतनी कमाई तो नहीं ही कर सकता है। यह मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार का नमूना है। 45-50 हजार की नौकरी करने वाला एक कॉन्स्टेबल महज कुछ सालों में ही अरबपति बन जाता है। हालांकि ये सब कुछ वह अपने बूते नहीं करता है, उसके बाद पावर कॉरिडोर के बड़े लोगों का भी हाथ है। तभी तो उनकी कॉलोनियों में वह आलीशान कोठी में रहता था, जिसके इंटीरियर पर कथित तौर पर दो करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। कॉन्स्टेबल तो भ्रष्टाचार के इस कुएं की छोटी मछली है जो कथित पंगे की वजह से फंस गया। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त हर दिन करीब आधा दर्जन भ्रष्ट लोगों को पकड़ रही है।

बड़े लोगों का मिला हुआ है आशीर्वाद

कथित तौर पर भोपाल के पावर कॉरिडोर में एक चर्चा है कि कॉन्स्टेबल के ऊपर कुछ बड़े लोगों का भी हाथ था। उनकी काली कमाई को भी पूर्व कॉन्स्टेबल रियल एस्टेट में निवेश करता था। हालांकि न तो लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। जंगल में लवारिश पड़ी कार से मिले सोने और कैश की पुष्टि भोपाल पुलिस ने कर दी है। बरामद लवारिश कार पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन सिंह गौर की है। गाड़ी पर हूटर लगी थी। साथ ही आरटीओ को बोर्ड लगा था।

साहबों के आशीर्वाद से नाकों की दलाली करता था कॉन्स्टेबल

पूर्व कॉन्स्टेबल को करीब से जानने वाले लोग नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि वह परिवहन विभाग में अपने आकाओं के आशीर्वाद से चेक पोस्ट पर दलाली करता था। अवैध दौलत उसने नाकों पर वसूली कर बनाई है। उसके रहन सहन से लेकर बाकी चीजों में बदलाव आने लगा तो शक बढ़ने लगा। इसके बाद उसने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

नेता, बिल्डर और अफसरों के कॉक्स पर भी छापेमारी

मध्य प्रदेश में सिर्फ कॉन्स्टेबल ही आईटी के रडार पर नहीं है। चार दिनों से एक और कॉक्स पर छापेमारी चल रही है। उसमें बिल्डर, नेता और अफसरों का गठजोड़ है। उस छापेमारी में भी छह करोड़ से अधिक कैश मिले हैं। कथित तौर पर उस छापेमारी के पूर्व मुख्य सचिव के तार भी जुड़ रहे हैं। उस कॉक्स ने भोपाल में बनने वाले एक बाइपास की जमीन खरीदने में खेल किया है। वह कार्रवाई पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शिकायत के बाद चल रही है।

आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हर विभाग!

कथित तौर पर मध्य प्रदेश के अधिकांश विभाग भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे हैं। दो दिन पहले कैग की रिपोई आई है। उसमें भी यही इशारा है। 38 मीट्रिक टन

अमान्य राशन पोषण आहार के नाम पर बांट दिए। बाइक से राशन की ढुलान करवाकर ट्रांसपोर्टेशन की राशि निकलवा ली।

बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं

एमपी लोकायुक्त जो कार्रवाई कर रही है, वह छोटी मछलियों पर कर रही है। हर दिन जो पकड़े जा रहे हैं, उनमें सीएमओ से लेकर पटवारी और बिजली विभाग के इंजीनियर तक होते हैं। लेकिन बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं डालती हैं। हाल ही में जबलपुर में एसडीएम का ड्राइवर केस सेटल करवाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। उसे लोकायुक्त ने दबोचा लेकिन मैडम तक नहीं पहुंच पाई। यह सुनकर आपको मजाक ही लगेगा कि क्या कोई ड्राइवर इतनी हिमाकत कर सकता है कि वह रिश्वत की इतनी बड़ी राशि वह ले। किसान वहां चीख-चीखकर कह रहा था कि एसडीएम मैडम के सामने तीन लाख रुपए में डील हुई थी लेकिन मैडम को सिर्फ वहां से खानापूर्ति के नाम पर हटाया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सोना मिलने वाले दिन भी पकड़े गए तीन भ्रष्टाचारी

वहीं, जिस दिन भोपाल के जंगल में 52 किलो सोना मिला। उस दिन भी मध्य प्रदेश में तीन भ्रष्टाचारी पकड़े गए। मैहर में एक नगर पालिका सीएमओ को 20,000 रुपए लेते पकड़ा गया। धार में एक वनपाल को 10000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जबलपुर में बिजली विभाग के इंजीनियर को 30,000 रुपए की राशि के साथ दबोचा गया। ये कार्रवाई सिर्फ बानगी है जो सिर्फ दिखावे के लिए है। बेखौफ भ्रष्टाचारियों ने पावन महाकाल लोक को भी नहीं छोड़ा है, जिसका उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक साल के अंदर ही मूर्तियां टूटकर गिरने लगीं। लोकायुक्त में शिकायत पड़ी है लेकिन नतीजे सिफर हैं। भ्रष्टाचार की बानगी गिनाने लगे तो शायद शब्द कम पड़ जाए लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। बीते कुछ महीनों की कार्रवाई को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 40-50 हजार की नौकरी करने वाले बाबू मध्य प्रदेश में जब करोड़पति हैं तो बाकियों का छोड़ दीजिए। शायद यही वजह है कि सत्ता के मठाधीशों के नाक नीचे बनी सड़कें एक बारिश नहीं झेल पाती है।

केंद्र ने भी मानी गड़बड़ी

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें हर तरफ हैं। कपास की खरीदी के नाम पर गड़बड़ी हुई। केंद्र ने भी इसे स्वीकार किया है। कार्रवाई चल रही है। नल जल योजना का एमपी में पलीता लग गया है। पैसे तो निकल गए लेकिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा। अब सत्ता और विपक्ष दोनों मांग कर रही है कि इसकी जांच की जाए।